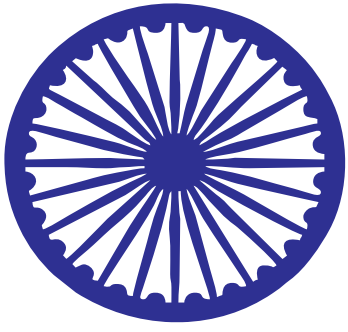




नवसर्जन संस्कृति

वर्ष : 01

अंक : 279

दि. 12.07.2026,

रविवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

# पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर तेज हुई सियासी जंग, संगठन की कमान से लेकर 2027 के मुख्यमंत्री चेहरे तक छिड़ी रणनीतिक लड़ाई

चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक नेतृत्व को लेकर लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी के भीतर जारी अड्डहमति ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने समर्थक नेताओं के साथ शनिवार को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल से मुलाकात कर अपनी राजनीतिक चिंताओं और मांगों को विस्तार से रखा। हालांकि कई घंटे चली चर्चा के बाद भी किसी तरह की सहमति नहीं बन सकी। अब इस पूरे विवाद पर अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर होने की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान चन्नी समर्थक नेताओं ने स्पष्ट रूप से दो प्रमुख मांगें रखीं। पहली मांग यह थी कि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िग को संगठन की कमान से हटाया जाए और नए नेतृत्व पर विचार किया जाए।

दूसरी मांग यह रखी गई कि यदि अध्यक्ष पद में बदलाव संभव नहीं है, तो पार्टी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का आधिकारिक चेहरा घोषित करे। साथ ही विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण और चुनावी रणनीति तय करने में उन्हें प्रमुख भूमिका दी जाए। इन मांगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विवाद केवल संगठनात्मक पद तक सीमित नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की संभावित दावेदारी को लेकर भी पार्टी के भीतर राजनीतिक समीकरण बनने लगे हैं। कांग्रेस के भीतर यह धारणा लंबे समय से रही है कि जिस नेता के नेतृत्व में संगठन चुनाव लड़ता है, चुनाव में सफलता मिलने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद पर उसकी दावेदारी स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाती है। यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चल रही रस्साकशी को केवल संगठनात्मक



नियुक्ति नहीं, बल्कि भविष्य की सत्ता की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बैठक से पहले मोडिया से बातचीत के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी का एक संक्षिप्त लेकिन चर्चित बयान भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा, “तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे।” राजनीतिक विश्लेषक इस टिप्पणी को पार्टी नेतृत्व के लिए एक संकेत और दबाव के रणनीति के रूप में देख रहे हैं। हालांकि

बड़े राजनीतिक फैसले लेने का अधिकार केवल कांग्रेस हाईकमान के पास है। ऐसे में अब यह पूरा मामला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विचार के लिए भेजे जाने की संभावना है। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर बढ़ी सक्रियता के पीछे छिले चुनावों का राजनीतिक अनुभव भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद से पंजाब कांग्रेस में यह धारणा और मजबूत हुई कि संगठन की कमान संभालने वाला नेता भविष्य में मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार बन जाता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चरणजीत सिंह चन्नी इसी राजनीतिक परंपरा को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति आगे बढ़ा रहे हैं। यदि उन्हें संगठन की कमान मिलती है तो विधानसभा चुनाव की तैयारी, टिकट वितरण, प्रचार अभियान, संगठनात्मक नियुक्तियों और चुनावी रणनीति पर उनका प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उनका दावा भी मजबूत हो सकता है। चन्नी समर्थकों का तर्क है कि पंजाब में कांग्रेस को फिर से मजबूत स्थिति में लाने के लिए संगठन में नए नेतृत्व की आवश्यकता है। उनका आरोप है कि मौजूदा प्रदेश नेतृत्व आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने में अपेक्षित आरोप है कि मौजूदा प्रदेश नेतृत्व आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने में अपेक्षित

कहना है कि यदि संगठन को नए नेतृत्व के साथ सक्रिय किया जाए तो कांग्रेस आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चरणजीत सिंह चन्नी इसी राजनीतिक परंपरा को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति आगे बढ़ा रहे हैं। यदि उन्हें संगठन की कमान मिलती है तो विधानसभा चुनाव की तैयारी, टिकट वितरण, प्रचार अभियान, संगठनात्मक नियुक्तियों और चुनावी रणनीति पर उनका प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उनका दावा भी मजबूत हो सकता है। चन्नी समर्थकों का तर्क है कि पंजाब में कांग्रेस को फिर से मजबूत स्थिति में लाने के लिए संगठन में नए नेतृत्व की आवश्यकता है। उनका आरोप है कि मौजूदा प्रदेश नेतृत्व आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने में अपेक्षित

कहना है कि यदि संगठन को नए नेतृत्व के साथ सक्रिय किया जाए तो कांग्रेस आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चरणजीत सिंह चन्नी इसी राजनीतिक परंपरा को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति आगे बढ़ा रहे हैं। यदि उन्हें संगठन की कमान मिलती है तो विधानसभा चुनाव की तैयारी, टिकट वितरण, प्रचार अभियान, संगठनात्मक नियुक्तियों और चुनावी रणनीति पर उनका प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उनका दावा भी मजबूत हो सकता है। चन्नी समर्थकों का तर्क है कि पंजाब में कांग्रेस को फिर से मजबूत स्थिति में लाने के लिए संगठन में नए नेतृत्व की आवश्यकता है। उनका आरोप है कि मौजूदा प्रदेश नेतृत्व आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने में अपेक्षित

## खामेनेई की मौत के बाद ईरान का सख्त संदेश, नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा ने प्रतिशोध का किया ऐलान, पश्चिम एशिया में फिर बढ़ा तनाव

तेहरान। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद देश के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि उनके पिता का खून व्यर्थ नहीं जाएगा और उनकी हत्या का बदला अवश्य लिया जाएगा। उन्होंने इसे केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की इच्छा और जिम्मेदारी बताया। उनके इस बयान ने पहले से तनावपूर्ण पश्चिम एशिया की स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।

राज्य संप्रति संदेश में मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि उनके पिता और अन्य मृतकों को खून का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि “शहीदों के खून का बदला लेना केवल एक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्र की मांग और हमारा कर्तव्य है।” उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान अपने ऊपर हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित समय पर कार्यवाई करेगा। हालांकि उन्होंने किसी संभावित सैन्य अभियान का विवरण नहीं दिया, लेकिन उनके बयान को ईरान की भविष्य की रणनीति का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।

मुज्तबा खामेनेई ने अपने संबोधन में कहा कि ईरान अपने नेताओं और नागरिकों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता कठिन परिस्थितियों में भी एकजुट होकर खड़ी है और बाहरी दबावों के सामने झुकने वाली नहीं है। उनके अनुसार ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी तथा देश किसी भी प्रकार के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अपने संदेश में नए सर्वोच्च नेता ने उन लाखों लोगों का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भाग लिया। उन्होंने कहा कि अंतिम विदाई में उमड़ी विशाल भीड़ ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि ईरान अपने नेतृत्व और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ मजबूती से खड़ा है। उनके अनुसार अंतिम संस्कार में लोगों की अभूतपूर्व भागीदारी ने देश की एकता, राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय संकल्प को प्रदर्शित किया है। ईरान में अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का अत्यधिक संकेत दिनों तक चला, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजधानी तेहरान से लेकर मशहद को ईरान की भविष्य की रणनीति का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।

देशों के बीच सैन्य टकराव, जवाबी कार्रवाई और संघर्ष विराम को लेकर कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। क्षेत्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि नए सर्वोच्च नेता के सख्त बयान के बाद पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निगाहें और अधिक केंद्रित हो सकती हैं। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से जारी तनाव भी इस घटनाक्रम के बाद नई दिशा ले सकता है। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान किस प्रकार की कार्रवाई करेगा, लेकिन मुज्तबा खामेनेई के बयान ने यह संकेत अवश्य दिया है कि तेहरान अपने शीर्ष नेतृत्व पर हुए हमले को भूल नहीं है और भविष्य की रणनीति में प्रतिशोध की भावना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षित, सुविधाजनक और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने ‘लेडीज स्पेशल’ बस सेवा के विस्तार का फैसला किया है, जिसके तहत हर ही 50 नई विशेष बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगीं। इन बसों का उद्देश्य महिला यात्रियों, विशेषकर छात्राओं और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। परिवहन विभाग ने इन बसों के संचालन की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इनके लिए उपयुक्त मांगों के चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार नई बसों को इस तरह संचालित किया जाएगा कि उन क्षेत्रों को प्राथमिकता मिले जहां बड़ी संख्या में महिलाएं प्रतिदिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करती हैं। प्रस्तावित योजना के तहत 50 बसों में से 25 बसें विशेष रूप से छात्राओं के लिए संचालित की जाएंगी। इन्हें यूनिवर्सिटी स्पेशल बस के रूप में चलाया जाएगा ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय, विभिन्न कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन सुविधा मिल सके।

शेष 25 बसों को बाहरी दिल्ली के उन इलाकों में चलाने की योजना बनाई गई है, जहां महिला यात्रियों की संख्या अधिक होने के बावजूद सार्वजनिक परिवहन के पर्याप्त विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। सरकार का मानना है कि बाहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए प्रतिदिन शहर के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करती हैं। ऐसे क्षेत्रों में विशेष बस सेवा शुरू होने से उनकी यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी।

परिवहन विभाग ने बताया कि कुछ संभावित मांगों की पहचान पहले ही कर ली गई है, जबकि अन्य मांगों के चयन के लिए विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि रूट तय करते समय केवल यात्रियों की संख्या ही नहीं, बल्कि महिलाओं की वास्तविक यात्रा आवश्यकताओं, भौडभाड़, परिवहन उपलब्धता और सुरक्षा संबंधी पहलुओं की भी ध्यान में रखा जा रहा है।

नई ‘लेडीज स्पेशल’ बसों में केवल महिला यात्रियों को यात्रा की अनुमति होगी। इन बसों में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगीं। हालांकि सरकार ने सुरक्षा उपायों का विस्तृत विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार इन बसों में महिला यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में विशेष व्यवस्था की जाएगी। इससे विशेष रूप से सुबह और देर रात यात्रा करने वाली महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली सरकार पहले भी सीमित स्तर पर ‘लेडीज स्पेशल’ बस सेवा संचालित करती रही है। अब इस सेवा को अधिक व्यवस्थित और व्यापक स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है। परिवहन विभाग का मानना है कि महिलाओं के लिए अलग बस सेवा उपलब्ध कहना है कि रूट तय करते समय केवल यात्रियों की संख्या ही नहीं, बल्कि महिलाओं की वास्तविक यात्रा आवश्यकताओं, भौडभाड़, परिवहन उपलब्धता और सुरक्षा संबंधी पहलुओं की भी ध्यान में रखा जा रहा है।

दिल्ली सरकार पहले भी सीमित स्तर पर ‘लेडीज स्पेशल’ बस सेवा संचालित करती रही है। अब इस सेवा को अधिक व्यवस्थित और व्यापक स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है। परिवहन विभाग का मानना है कि महिलाओं के लिए अलग बस सेवा उपलब्ध कहना है कि रूट तय करते समय केवल यात्रियों की संख्या ही नहीं, बल्कि महिलाओं की वास्तविक यात्रा आवश्यकताओं, भौडभाड़, परिवहन उपलब्धता और सुरक्षा संबंधी पहलुओं की भी ध्यान में रखा जा रहा है।

दिल्ली सरकार पहले भी सीमित स्तर पर ‘लेडीज स्पेशल’ बस सेवा संचालित करती रही है। अब इस सेवा को अधिक व्यवस्थित और व्यापक स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है। परिवहन विभाग का मानना है कि महिलाओं के लिए अलग बस सेवा उपलब्ध कहना है कि रूट तय करते समय केवल यात्रियों की संख्या ही नहीं, बल्कि महिलाओं की वास्तविक यात्रा आवश्यकताओं, भौडभाड़, परिवहन उपलब्धता और सुरक्षा संबंधी पहलुओं की भी ध्यान में रखा जा रहा है।

## राम मंदिर ट्रस्ट में नए CEO की तलाश तेज, पारदर्शी चयन प्रक्रिया शुरू चंदा विवाद के बीच प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के चयन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब हाल ही में मंदिर से जुड़े चंदे में कथित अनियमितता के आरोपों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ट्रस्ट ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि भविष्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह तथा सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से योग्य और अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इसी दिशा में गठित तीन सदस्यीय सचं कमिटी ने शनिवार को नई दिल्ली में अपनी पहली बैठक आयोजित कर चयन प्रक्रिया की रूपरेखा तय की।

ट्रस्ट की ओर से गठित इस सचं कमिटी में जम्मू-कश्मीर एवं पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) प्रमोद कुमार, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) विष्णुकान्त चतुर्वेदी तथा श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सुश्रुत हावड़े को शामिल किया गया है। समिति को ऐसे व्यक्ति की तलाश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय प्रबंधन, धार्मिक संस्थानों के संचालन और संगठनात्मक नेतृत्व का व्यापक अनुभव रखता हो। सूत्रों के अनुसार पहली बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए पात्रता, अनुभव, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति की शर्तों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने इस बात पर सहमति बनाई कि पद की जिम्मेदारियों को देखते हुए उम्मीदवार का प्रशासनिक दृष्टिकोण मजबूत होना चाहिए और वह बड़े स्तर पर संस्थागत कार्यों का संचालन करने में सक्षम हो। इसी कारण न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है। इसके साथ ही प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, सार्वजनिक संस्थान अथवा बड़े संगठन के संचालन में कम से कम 20

वर्षों का अनुभव अनिवार्य रखा गया है। जिन उम्मीदवारों के पास मंदिर प्रबंधन, धार्मिक ट्रस्टों या बड़े आध्यात्मिक संस्थानों के संचालन का अनुभव होगा, उन्हें समय प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलने की संभावना है। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी तक सीमित नहीं होगा, बल्कि मंदिर परिसर के संचालन, श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं, वित्तीय पारदर्शिता, विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी, ट्रस्ट के दैनिक कार्यों के समन्वय और भविष्य की वैकल्पिक योजनाओं के क्रियान्वयन में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यही कारण है कि चयन प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित और योग्यता आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवेदन करने वाला अस्थायी हिंदू धर्म का अनुयायी होना चाहिए। ट्रस्ट ने आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई निर्धारित की है। आवेदन प्राप्त करने के लिए जल्द ही एक अधिकृत ई-मेल आईडी जारी की जाएगी, जिसके माध्यम से इच्छुक उम्मीदवार अपने दस्तावेज और आवेदन भेज सकेंगे। आवेदन प्राप्त होने के बाद सचं कमिटी सभी अर्हताओं की योग्यता, अनुभव और उपलब्धियों का विस्तृत मूल्यांकन करेगी। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेकर अंतिम नाम ट्रस्ट के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। चयनित मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अयोध्या में रहकर अपनी सेवाएं देनी होंगी। ट्रस्ट का मानना है कि मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों और दैनिक प्रशासनिक गतिविधियों की प्रभावी निगरानी के लिए अधिकारी का स्थायी स्तर पर उपलब्ध रहना आवश्यक है। प्रारंभिक नियुक्ति तीन वर्षों के लिए की जाएगी। कार्यकाल के दौरान

प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। चयन प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सचं कमिटी एक सचिव की भी नियुक्ति करेगी, जो आवेदन प्राप्त करने, दस्तावेजों के परीक्षण और प्रशासनिक समन्वय का कार्य संभालेगा। ट्रस्ट का लक्ष्य अमले लाभण एक महीने के भीतर पूरी चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति ऐसे समय की जा रही है, जब मंदिर से जुड़े चंदे में कथित हेराफेरी के आरोपों ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि चयन प्रक्रिया जारी है, लेकिन ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नूपेंद्र मिश्रा ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण के लिए दिया उम्मीदवार अपने दस्तावेज और आवेदन भेज सकेंगे। आवेदन प्राप्त होने के बाद सचं कमिटी सभी अर्हताओं की योग्यता, अनुभव और उपलब्धियों का विस्तृत मूल्यांकन करेगी। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेकर अंतिम नाम ट्रस्ट के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। चयनित मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अयोध्या में रहकर अपनी सेवाएं देनी होंगी। ट्रस्ट का मानना है कि मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों और दैनिक प्रशासनिक गतिविधियों की प्रभावी निगरानी के लिए अधिकारी का स्थायी स्तर पर उपलब्ध रहना आवश्यक है। प्रारंभिक नियुक्ति तीन वर्षों के लिए की जाएगी। कार्यकाल के दौरान

प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। चयन प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सचं कमिटी एक सचिव की भी नियुक्ति करेगी, जो आवेदन प्राप्त करने, दस्तावेजों के परीक्षण और प्रशासनिक समन्वय का कार्य संभालेगा। ट्रस्ट का लक्ष्य अमले लाभण एक महीने के भीतर पूरी चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति ऐसे समय की जा रही है, जब मंदिर से जुड़े चंदे में कथित हेराफेरी के आरोपों ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि चयन प्रक्रिया जारी है, लेकिन ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नूपेंद्र मिश्रा ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण के लिए दिया उम्मीदवार अपने दस्तावेज और आवेदन भेज सकेंगे। आवेदन प्राप्त होने के बाद सचं कमिटी सभी अर्हताओं की योग्यता, अनुभव और उपलब्धियों का विस्तृत मूल्यांकन करेगी। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेकर अंतिम नाम ट्रस्ट के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। चयनित मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अयोध्या में रहकर अपनी सेवाएं देनी होंगी। ट्रस्ट का मानना है कि मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों और दैनिक प्रशासनिक गतिविधियों की प्रभावी निगरानी के लिए अधिकारी का स्थायी स्तर पर उपलब्ध रहना आवश्यक है। प्रारंभिक नियुक्ति तीन वर्षों के लिए की जाएगी। कार्यकाल के दौरान

नवसर्जन संस्कृति

हिन्दी

JioTV

CHENNAL NO. 2063

Jio Air Fiber

Jio tv +

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba Tv

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Roku Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये



## संपादकीय

### ज़्यादा अल्कोहल वाली दवाओं का नियमन सराहनीय

सार्वजनिक विमर्श में लंबे समय से मांग की जाती रही है कि ज्यादा अल्कोहल की मात्रा वाली दवाओं का सख्ती से नियमन किया जाए। दरअसल, नशे की लत छुड़ाने के प्रयासों के दौरान इन दवाओं का दुरुपयोग किया जाता रहा है। साथ ही जिन राज्यों में नशाबंदी लागू है, वहां भी उनके गलत इस्तेमाल की शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का ज्यादा अल्कोहल की मात्रा वाली पीने वाली दवाइयों व सिरप की बिक्री पर सख्ती करने का फैसला, एक जरूरी सुधार है। निश्चय ही इस कदम से लंबे समय से इन दवाइयों के गलत इस्तेमाल की प्रवृत्ति पर रोक लग सकेगी। दरअसल, 12 प्रतिशत से ज्यादा एंथिल अल्कोहल मात्रा के साथ बड़ी बोलतल में मिलने वाली दवाइयों के लिये अब लाइसेंस, डॉक्टर की पर्ची और रिकाईर्ड रखने के नियम कड़े करके सरकार ने जरूरी पहल की है। आखिरकार सरकार ने उस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, जिसे रेगुलेटर लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। यह हकीकत है कि इन दवाओं का नियमन व निगरानी कायदे की न होने से ये दवाएं नशा करने का जरिया भी बन रही थीं। निश्चित रूप से ये नये नियम मरीजों की दवा तक पहुंच और जन-सुरक्षा के बीच समझदारी बर्रा संतुलन बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन्हें वास्तव में इन दवाइयों की जरूरत है, उन्हें ये दवाइयां डॉक्टर की देखरेख में सहज उपलब्ध हो सकेंगी। वहीं दूसरी ओर इन दवाइयों का दुरुपयोग गलत कार्य के लिये करने वालों की इन तक पहुंच मुश्किल हो जाएगी। निश्चय ही यह वक्त की जरूरत थी क्योंकि किशोर और नशे की लत से जुड़ा रहे लोग अक्सर ऐसी दवाइयों को शराब के सस्ते विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने लगते हैं। जनमानस में उधार के लिये आम बोलचाल में प्रचलित शब्द ‘दवा-दारू’, वास्तव में ऐसे नशेड़ियों के लिये नशे का मौका उपलब्ध कराने का जरिया बन जाता था। इस पर अंकुश लगाना निश्चय ही स्वागत योग्य कदम है। दरअसल, एम्वस दिल्ली की नेपेवल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ने नशीले पदार्थों की लत छुड़ाने के लिये इलाज करा रहे लोगों के बीच इन दवाइयों व कफ सिरफ आदि के अजुचित इस्तेमाल का पर्याप्त रिर्काईर्ड रखा है। इतना ही नहीं, जन स्वास्थ्य से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस बाबत चिंता जाहिर कर चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो बाकायदा चेतावनी दी है कि जिन जगहों पर सामान्य शराब महंगी होती है या नशाबंदी लागू होने से आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, वहां अधिक अल्कोहल वाली दवाइयों के दुरुपयोग की लगातार संभावना बनी रहती है। जो इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है कि जैसे-जैसे नशीले पदार्थों के रूप में दवाइयों का दुरुपयोग बढ़ता है, वैसे-वैसे ही नियमों में बदलाव करना अपरिहार्य हो जाता है। बहरहाल, कागजों पर नियम बना देना तो मात्र एक शुरुआत भर है। सबसे जरूरी है कि इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही निगरानी तंत्र को भी मजबूत बनाने की जरूरत है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि नियमों को तोड़कर दवा के दुरुपयोग की कोशिश करने वालों की निगरानी के लिये ड्रग इस्पेक्टरों की पर्याप्त संख्या हो। इसके अलावा फार्मसियों को भी इस बाबत जवाबदेह बनाना जरूरी हो जाता है। जिसके लिये ऐसी दवाइयों की बिक्री के रिकाईर्ड को डिजिटल करना भी आवश्यक है ताकि नियामक तंत्र इनकी बिक्री की निगरानी कर सके। निस्संदेह, डॉक्टरों का भी नैतिक दायित्व है कि वे जरूरतमंद लोगों को ये दवाइयां सौच-समझकर ही लीखें। साथ ही इससे होने वाले खतरों के बारे में भी मरीजों को अवगत कराएं। इन बातों पर दवा का लेवल लगाने का अंतिम निष्कर्ष यह नहीं है कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बहरहाल, नियमों में बदलाव सरकार का एक बुनियादी जिम्मेदारी को ही दर्शाता है। जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि इलाज के लिए उपयोग होने वाले उत्पादों से लोगों को फायदा ही हो, नुकसान नहीं। निस्संदेह, सरकार ने सही दिशा में कदम उठाया है। अब इस नियम को सख्ती से लागू करने का पक्का इरादा भी दिखाना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस रोग का पूरा इलाज नहीं हो पायेगा।

## अभियान

### रहस्यों, आस्था और अद्भुत परंपराओं का संगम है श्रीजगन्नाथ धाम, सदियों से दुनिया को चकित कर रहे हैं पुरी मंदिर के अनसुलझे रहस्य

भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में कुछ ऐसे तीर्थस्थल हैं, जिनके प्रति श्रद्धा केवल धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी परंपराएं, स्थापत्य कला और उनसे जुड़े रहस्य भी लोगों को आकर्षित करते हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान श्रीजगन्नाथ का पवन धाम ऐसा ही एक दिव्य तीर्थ है, जहां हिंदू धर्म के चार प्रमुख धामों में विश्व स्थान प्राप्त है। इसे धरती का वैदूत भी कहा जाता है। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु यहां भगवान श्रीजगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। समुद्र तट पर स्थित यह विशाल मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि वास्तुकला, इतिहास, परंपराओं और अनसुलझे रहस्यों का अद्भुत संगम भी माना जाता है। यही कारण है कि सदियों बाद भी श्रीजगन्नाथ मंदिर को लेकर लोगों की जिज्ञासा बनी हुई है। मान्यता है कि भगवान श्रीजगन्नाथ, भगवान श्रीरंगनाथ की एक विशेष स्वरूप हैं। मंदिर के गभीर में भगवान विष्णुवास, बलभद्र और देवी सुभद्रा की काष्ठ निर्मित प्रतिमाएं विराजमान हैं। दुनिया के अधिकांश मंदिरों में पत्थर या धातु की मूर्तियां स्थापित होती हैं, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां भगवा की प्रतिमाएं नैम की पर्वत लकड़ी से बनाई जाती हैं। इसे निश्चित अवधि के बाद विशेष धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से बदला जात है। इस प्रक्रिया को नवकरंकर कहा जात है। सामान्यतः यह आयोजन 12 से 19 वर्ष के

बीच उस वर्ष होता है, जब आषाढ़ महीने में अधिक मास पड़ता है। पुराने विग्रहों से दिव्य तत्व को नए विग्रहों में स्थापित करने की परंपरा विश्व की सबसे अद्भुत धार्मिक प्रक्रियाओं में गिनी जाती है। भगवान जगन्नाथ की अधुरी प्रतिात होने वाली प्रतिमाओं के पीछे भी एक अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक कथा प्रचलित है। मान्यता के अनुसार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा से प्रतिमाओं के निर्माण का अनुरोध किया। विश्वकर्माने एक शर्त रखी कि वे बंद कमरे में बिना किसी व्यवधान के मूर्तियों का निर्माण करेंगे और जब तक कार्य पूरा न हो जाए, कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। कई दिनों तक भीतर से कोई आवाज न आने पर राजा और रानी चिंतित हो उठे। उत्सुकतावश उन्होंने निर्धारित समय से पहले द्वार खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला, भगवान विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और प्रतिमाएं अधुरी अवस्था में ही रह गईं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान ने स्वयं इसी स्वरूप में विराजमान रहने की इच्छा व्यक्त की, इसलिए आज भी अधुरी भुजाओं और विशिष्ट आकृति वाली इन्हीं प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। पुरी धाम की सबसे प्रसिद्ध परंपरा विश्वविख्यात रथ यात्रा है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा भय्य रथों पर सवार होकर मुख्य मंदिर से गुँडिच मंदिर तक यात्रा करते हैं। इसे भगवान की अपनी मौसी के घर की यात्रा भी कहा

जाता है। लाखों श्रद्धालु विशाल रथियों से रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए दूर-दूर से पुरी पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता है कि रथ की रस्सी को सफ़र कराने की अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। नि दिनों तक गुँडिच मंदिर में विराजमान रहने के बाद भगवान पुनः मुख्य मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। यह उत्सव केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के अनेक देशों में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जात है।श्रीजगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थापित विशाल सुदर्शन चक्र भी अपने आप में खूबी कि वे बंद कमरे में बिना किसी व्यवधान के अमृता आश्चर्य माना जाता है। रथों में फीट ऊंचा और कई टन वजनी यह धातु का चक्र मंदिर की सबसे ऊँची चोटी पर स्थापित है। श्रद्धालुओं का कहना है कि आप पुरी शहर में किसी भी दिशा में खड़े होकर इसे देखें, ऐसा प्रतीत होता है जैसे चक्र आपकी ओर ही मुघ्न किए हुए है। इस विशेष दृश्य प्राप्त ने सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित किया है। धार्मिक दृष्टि से सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के शिखर पर प्रतिदिन बदला जाने वाला ध्वज भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। कई से फीट ऊंचाई पर बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के प्रशिष्ठित सेवकयंत्र प्रतिदिन मंदिर के शिखर पर चढ़कर नया ध्वज स्थापित करते हैं। यह परंपरा सदियों से बिना किसी व्यवधान के चली आ रही है। लोकमान्यता है कि यदि किसी दिन ध्वज परिवर्तन न हो, तो मंदिर

को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ सकता है। ध्वज को लेकर यह भी प्रसिद्ध मान्यता है कि यह द्वाक ही दिशा के विपरीत लहराता हुआ दिखाई नहीं देते। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के अलग-अलग मत हैं। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान की दिव्य लीला का प्रतीक माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर की विशाल रथोंई विश्व की सबसे बड़ी मंदिर रथोंईयें मे गिनी जाती है। यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद तैयार किया जात है। विशेष बात यह है कि भोजन आज भी पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। रथों में एक के ऊपर एक कई मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं और आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन पहले पक जाता है, जबकि सबसे नीचे रखा बर्तन सबसे बाद में पकता है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसे श्रद्धालु भगवान की विशेष कृपा मानते हैं। मंदिर में तैयार होने वाला महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि भगवान का प्रसाद माना जाता है। यहां छग्न भोग सहित अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। यह भी प्रसिद्ध मान्यता है कि चाहे श्रद्धालुओं की संख्या कितनी भी अधिक क्यों न हो, महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। वहीं मंदिर के पट बंद होने तक प्रसाद पूरी तरह वितरित हो जात है और भोजन व्यर्थ नहीं जाता। श्रद्धालु इसे माता अनुष्णा और माता लक्ष्मी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। मंदिर की रथों में सेवा करने वाले सैकड़ों रसोइये पीड़ियों से

इसी परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। श्रीजगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक और लोकप्रिय रहस्य यह है कि मंदिर के ऊपर पक्षी उड़ते हुए दिखाई नहीं देते। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के ऊपर पक्षियों का बैठना या उड़ना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर से किसी विमान का निर्यमित मार्ग नहीं बनाया गया है। इन मान्यताओं को लेकर समय-समय पर अनुष्णा-अलग चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि विमान मार्गों का निर्धारण नगरिक उड्डयन के नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुसार होता है तथा पक्षियों से जुड़ी मान्यता के वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी यह विश्व श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। मंदिर के संबंध में एक और लोकप्रिय धारणा यह भी है कि इसकी परछाई स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। वास्तव में मंदिर की विशाल संरचना, ऊंचाई, आसपास की इमारतों, सूर्य की दिशा और प्रकाश के कोण के कारण सामान्य दृष्टि से इसकी छाया स्पष्ट रूप में देख पाना कठिन होता है। समय के साथ यह बात एक रहस्य के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इसी प्रकार मंदिर के सिंहद्वार के भीतर प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज कम सुनाई देने और बाहर निकलते ही पुनः स्पष्ट दिखाई देने की मान्यता भी श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। श्रीजगन्नाथ मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं,

बल्कि भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। लगभग 65 मीटर ऊंचा इसका शिखर दूर से ही दिखाई देता है। मंदिर का निर्माण कर्ण शैली की वास्तुकला में किया गया है, जिसमें विशाल पत्थरों की जटिल नक्काशी, भव्य प्रवेश द्वार और अलौकिक शिल्पकला आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। सदियों पहले बिना आधुनिक तकनीक के निर्मित यह मंदिर भारतीय शिल्पकारों की अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण है। जगन्नाथ धाम की परंपराएं केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं हैं। बल्कि यहां सेवा का एक अनूठी व्यवस्था भी है। मंदिर में विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग परिवार पीढ़ियों से अपनी जिम्मेदारियां निभाते आ रहे हैं। कोई भगवान के वस्त्रों की सेवा करता है, कोई भोग तैयार करता है, कोई रथ निर्माण में योगदान देता है तो कोई दैनिक पूजा-अर्चना की व्यवस्था संभालता है। यह परंपरा भारतीय संस्कृति में गुरु-शिष्य और परिवार आधारित सेवा व्यवस्था का जीवंत उदाहरण मानी जाते हैं। आज भी पुरी का श्रीजगन्नाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल मंदिर के दर्शन ही नहीं करता, बल्कि सदियों से चली आ रही उन परंपराओं, रहस्यों और आध्यात्मिक अनुभवों को भी महसूस करता है, जिन्होंने इस धाम को विश्वभर में अद्वितीय पहचान दिलाई है।

प्रक्षेपक तथा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस किया गया है। यही कारण है कि यह दवा, समुद्र की सहार और समुद्र के भीतर छिपे दुश्मनों पर एक साथ प्रभावी प्रहार करने में सक्षम है। हम आपको बता दें कि महेंद्रगिरि को ब्लू वाटर युद्धपोत की श्रेणी में रखा गया है। इसका अर्थ है कि यह केवल तटीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर गहरे समुद्र में कई सप्ताह तक लगातार अभियान चलाने की क्षमता रखता है। खोज और बचाव अभियान, मानवीय सहायता, आपदा राहत, समुद्री सुरक्षा तथा हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी तैनाती जैसे दायित्व भी यह समान दक्षता से निभा सकता है। पूर्वी घाट पर की महेंद्रगिरि पर्वतमाला के नाम पर रखे गए इस युद्धपोत के प्रतीक चिह्न में दर्शाया गया शिकरा पैनी दृष्टि, धैर्य और निर्णायक प्रहार का प्रतीक है, जो इसकी युद्धक भूमिका को भी प्रतिबिंबित करता है। इतिहास देखा जाये तो महेंद्रगिरि का सामरिक महत्व केवल इसकी मारक क्षमता तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर आज विश्व व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और

सामरिक प्रतिस्पर्धा का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। ऐसे समय में भारत सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरि को पूर्वी बड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट सत्रह ए के तहत निर्मित यह छठा और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत सिर्फ एक नया जहाज नहीं, बल्कि समुद्री शक्ति, स्वदेशी रक्षा निर्माण और सामरिक आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक है। महेंद्रगिरि के नौसेना में शामिल होने के साथ ही भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह केवल अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दूरस्थ समुद्री क्षेत्रों में भी अपने हितों को प्रभावी सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हम आपको बता दें कि करीब छह हजार साल की सभ्यता और अट्हाइस नॉट की अधिकतम की पुष्टि करती है। जिन्होंने संसार को नई दिशा दी, वे कभी न कभी असफल हुए थे। अंतर केवल इतना था कि उन्होंने अपनी असफलताओं को अपनी फेहन नहीं बनने दिया। उन्होंने उन्हें सीख में बदला और फिर इस अनुभव के आधार पर नई सफलता का निर्माण किया। यही कारण है कि उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।

# श्री अमित शाह के ‘हरियाली लोकसभा’ प्रोजेक्ट के तहत बड़े पैमाने पर स्थानीय प्रजातियों के पेड़-पौधे लगाए जाएंगे

►► विभिन्न प्रजातियों के पशु-पक्षियों, तितलियों और कीटों को आकर्षित करने वाले स्थानीय प्रजातियों के पेड़-पौधे लगाने से गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ‘बसंत’ वापस आएगा

►► केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा उनके गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस वर्ष सवा करोड़ (1.25 crore) से अधिक वृक्ष-पौधे लगाने के लिए अभियान शुरू किया गया है और गांधीनगर को देश का एक मॉडल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनाने का संकल्प किया गया है।

►► जलवायु परिवर्तन के कारण समग्र दुनिया प्रभावित हुई है। इस परिवर्तन से लड़ने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पेड़ लगाने का देश का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है।

►► गांधीनगर हरियाली लोकसभा प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में गुजरात वन विभाग की 82 साइटों पर लगाए जा रहे लगभग 60 लाख पौधों में से 6.05 लाख से अधिक पौधे 24 दुर्लभ, संकटग्रस्त और विलुप्तप्राय देसी प्रजातियों के हैं।

गांधीनगर, 11 जुलाई : कुछ दिन पहले यदि आप बगोदरा से नल सरोवर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित कणोतर गाँव की 35 हेक्टेयर गौचर भूमि के बगल से गुज़रे होते, तो बहुत कम लोगों को वहाँ रहने का मन होता, क्योंकि बहुत ही क्षारयुक्त तथा जंगली बबूल से घिरी हुई यह भूमि उजाड़ जैसी थी। हालाँकि आज इस स्थल से गुज़रने वाला कोई भी व्यक्ति बिना रुके नहीं रह सकता।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के महत्वाकांक्षी ‘गांधीनगर हरियाली लोकसभा’ अभियान अंतर्गत गुजरात वन विभाग ने इस 25 हेक्टेयर भूमि का कायाकल्प कर दिया है। जंगली बबूल हटाकर, पथरीली और कठोर मिट्टी की गहरी जुताई की गई है और उसके बाद क्षारयुक्त भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जिप्सम, गोबर की खाद, आवश्यक पोषक तत्व और उर्वरक डालकर भूमि सुधार का कार्य किया गया। अब इस नवसाध्य भूमि में 2.30 लाख पेड़-पौधे लगाने का कार्य शुरू किया गया है। इनमें मुख्य रूप से स्थानीय प्रजातियों के पेड़-पौधों का रोपण किया जाएगा। इस 35 हेक्टेयर गौचर भूमि को चारों ओर से फेंसिंग कर सुरक्षित किया गया है। वृक्षों को पानी उपलब्ध कराने के लिए एक बोरेवेल बनाया गया है और विजली आपूर्ति के लिए एक सोलर प्लांट स्थापित किया गया है।

यह दृश्य केवल कणोतर गाँव तक



सीमित नहीं है, बल्कि श्री अमित शाह के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले अहमदाबाद तथा गांधीनगर जिलों के 82 स्थानों पर यह कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। पूरी तरह वीरान और खारी भूमि का पुनर्जीवन कर वहाँ स्थानीय प्रजातियों के पेड़-पौधे लगाए जा रहे हैं और नया इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के ‘गांधीनगर हरियाली लोकसभा प्रोजेक्ट’ के तहत इस वर्ष सवा करोड़ पौधे लगाने

का लक्ष्य है। इस लक्ष्य में वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों के 82 स्थानों पर 540.92 हेक्टेयर क्षेत्र में 60 लाख पेड़-पौधे लगाएगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान द्वारा अपने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र को देश के सबसे हरियाले लोकसभा क्षेत्रों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी पहल की है। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध इस अभियान के अंतर्गत इस वर्ष समग्र गांधीनगर

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे।

**बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान में स्थानीय प्रजातियों पर अधिक बल**

गांधीनगर हरियाली लोकसभा प्रोजेक्ट में स्थानीय तथा विलुप्त होती वनस्पतियों की प्रजातियों के रोपण पर विशेष बल दिया गया है।

गुजरात के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव श्री विनोद राव ने कहा, “इस अभियान अंतर्गत तेजी



से बढ़ने वाले वृक्षों के बजाय हमने अहमदाबाद एवं गांधीनगर जिलों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वृक्षों का चयन किया है। वन विभाग द्वारा कुल 121 वनस्पति प्रजातियों का रोपण किया जाएगा, जिनमें लगभग 80 प्रजातियाँ स्थानीय होंगी। इतना ही नहीं, लगाए जाने वाले 60 लाख पौधों में से 6.05 लाख से अधिक पौधे 24 दुर्लभ, संकटग्रस्त और विलुप्तप्राय देसी प्रजातियों के हैं।”

स्थानीय वनस्पति प्रजातियों में कुमकुम (Mallotus spp.), शिमली, कैंपली, कीलाई, चमुली, जंगली सहजन, सफेद सिरिश, जंगली

जामफल, कचनार, पीला केसूड़ा / टेसू, रीठा, सफेद साग तथा सफेद गंधार आदि शामिल हैं।

वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव श्री विनोद राव ने कहा, “देसी वृक्षों की बुवाई वन्यजीवों की विविधता को समर्थन देने वाले प्राकृतिक आवासों को पुनर्स्थापित कर इकोसिस्टम को पुनः विकसित करने में मदद करती है। देसी वृक्ष स्थानीय पक्षियों, सरीसृपों, तितलियों, मधुमक्खियों तथा अन्य पॉलीनेटर्स को भोजन, आश्रय और प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “स्थानीय वनस्पतियों के फूल, फल और पत्तियाँ पूरे वर्ष कीटों व पक्षियों को पोषण देते हैं, जबकि घनी वनस्पति छोटे जीवों के लिए सुरक्षित मार्ग बनाती है। नवसाध्य भूमि, नमी बनाए रखने की क्षमता तथा जैव विविधता इन आवासों को और अधिक सशक्त बनाती है, जिससे वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अधिक मजबूती से सामना कर सकते हैं।”

जैसे-जैसे वे पौधे बड़े होंगे, वैसे-वैसे वे स्थानीय स्तर पर संतुलन को पुनर्जीवित करेंगे, परागण को बढ़ाएंगे और एक समृद्ध तथा अत्यनिर्भर इकोसिस्टम बनाएंगे।

## भावनगर मंडल को मिली बड़ी उपलब्धि : धंधुका ट्रेक्शन सब-स्टेशन (TSS) का 2×25 केवी प्रणाली पर सफल बैक चार्ज

यात्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय एवं उच्च क्षमता वाली रेल सेवाएं उपलब्ध कराने तथा आधुनिक रेल विद्युतीकरण अवसंरचना को और अधिक सुरदृढ़ बनाने की दिशा में पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (ट्रेक्शन) श्री विजेंद्र कुमार मीणा के नेतृत्व एवं देखरेख में दिनांक 09 जुलाई को धंधुका ट्रेक्शन सब-स्टेशन (TSS) का 2×25 केवी ट्रेक्शन प्रणाली के अंतर्गत सफलतापूर्वक बैक चार्ज किया गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि धंधुका ट्रेक्शन सब-स्टेशन का सफल बैक चार्ज बोटाद-गांधीग्राम रेलखंड पर 2×25 केवी ट्रेक्शन प्रणाली के अंतर्गत ओवरहेड उपकरण (OHE) को चार्ज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक उपलब्धि है। इससे इस रेलखंड पर आधुनिक ट्रेक्शन प्रणाली के क्रियान्वयन को नई गति मिलेगी तथा भविष्य में रेल परिचालन अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय, ऊर्जा दक्ष एवं कुशल बनाया जा सकेगा।



उन्होंने बताया कि 2×25 केवी ट्रेक्शन प्रणाली पारंपरिक रेल विद्युतीकरण प्रणाली की तुलना में अधिक क्षमता,

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने विद्युत विभाग तथा

परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि धंधुका ट्रेक्शन सब-स्टेशन का सफल बैक चार्ज भावनगर मंडल में आधुनिक रेल अवसंरचना के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात बोटाद-गांधीग्राम रेलखंड पर रेल परिचालन और अधिक विश्वसनीय, सुरक्षित, तीव्र एवं प्रभावी होगा तथा यात्रियों को बेहतर सेवाओं का लाभ मिलेगा।

पश्चिम रेलवे का भावनगर मंडल भारतीय रेल के आधुनिकीकरण, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों के उपयोग तथा विश्वस्तरीय रेल अवसंरचना के विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। धंधुका ट्रेक्शन सब-स्टेशन का सफल बैक चार्ज इसी प्रतिबद्धता का एक सशक्त उदाहरण है, जो भविष्य में क्षेत्र के रेल परिचालन को नई गति प्रदान करने के साथ-साथ यात्रियों को अधिक सुरक्षित, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण रेल सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

2006 में तत्कालीन जल आपूर्ति मंत्री नरोत्तम पटेल के निर्देशों के बाद शुरू हुई बाढ़ की आपदा आज तक शरीर है। इसके बावजूद, लोग अब शासकों की आलोचना कर रहे हैं और उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन चूँकि लोग चुनावों में बड़ी संख्या में भाजपा को वोट देते हैं, इसलिए शासक अक्षम और गैर-जिम्मेदार हो गए हैं। और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। इस समस्या को देखते हुए, नागरिकों के हितों के लिए लड़ने वाले सामाजिक सेवा संगठन विकास ग्राहक सुरक्षा और अनुसंधान केंद्र के दक्षिण गुजरात अध्यक्ष छगनलाल डी. मेवाड़ा ने 2016 में गुजरात उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जो दस साल बीत जाने के बावजूद आज भी गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित है, क्योंकि अधिकारियों ने इस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

इस जनहित याचिका को दायर करने का मुख्य कारण यह है कि उकाई बांध का पानी सानिया हेमाद से कुम्भारिया, सरोली, दुनभल आदि से होकर बहने वाली खाड़ियों में जाता है। इन खाड़ियों पर बने अवैध बाजारों और बस्तियों को हटाने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत और सूदा की है, लेकिन कुम्भारिया-सरोली ग्राम पंचायत

और सूदा के नियंत्रण में आने वाली खाड़ियों में श्याम सिंगीनी टेक्सटाइल मार्केट और सारथी रैसिडेंस कुम्भारिया खाड़ी पर बने हुए हैं। कंकरापारा और सानियाग्राम से आने वाली सारथी नदी से कुम्भारिया के मोड़ पर दबाव शुरू हो गया है, जहां मीठी और कोयली खाड़ियों के दोनों किनारों पर बिल्डरों और अन्य लोगों द्वारा अवैध रूप से दुकानें, मकान और घर बनाए गए हैं। अवैध रूप से निर्मित भूमि बाजार के दूसरी ओर स्थित मागोब, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक अमर सिंह जिन्ना की सरकारी जमीन पर सरकार द्वारा आवंटित जगह का इस्तेमाल करके एससी/एसटी और सिद्धार्थ गैस एजेंसी चलाई जा रही है। आदिवासियों ने आजीविका चलाने की मांग की थी, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा आवंटित भूमि से चार गुना अधिक भूमि आवंटित की गई। उन्होंने उस पर पेट्रोल पंप बनाकर उसे बेच दिया। अब इसे 'अंबर हाउस' के नाम से जाना जाता है। यह देखकर दुख होता है कि कोयली नाले पर बड़े दबाव के कारण अन्य लोगों को परेशानी डोलनी पड़ रही है। दो दशक बीत चुके हैं। सबसे पहले तो जिम्मेदार कलेक्टर की जिम्मेदारी आती है। पिछले कलेक्टर से लेकर अब तक सेवा दे चुके कलेक्टर तक, यह जिम्मेदारी उन्हीं की है। अगर नाले का

निरीक्षण किया गया होता, तो आज यह स्थिति नहीं होती। सूरत नगर निगम में शामिल होने से नगर का विस्तार हुआ है, और इसमें शामिल गांवों के विकास की जिम्मेदारी सूरत नगर निगम की है। उस जमाने के कमिश्नर और उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों, विशेषकर रिश्तखोर अधिकारी, बिल्डरों की गोद में बैठे निर्लंबित जोन प्रमुख विपुल गणेशवाला की वजह से 45 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मौजूदा अधिकारियों की लापरवाही के कारण छोटे-बड़े व्यापारियों को लाखों-करोड़ों का नुकसान हुआ है। यह सब इन्हीं अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ है। स्थानीय पार्श्वों को सारी जानकारी होने के बावजूद, यह जानते हुए भी कि किसने कहाँ और कितना दबाव डाला है, भ्रष्टाचार हुआ है। जिसके कारण नुकसान हुआ है और निर्दोष जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता को जागरूक होना चाहिए और स्थानीय पार्श्व खाली फोटो दिखाकर दुख होता है कि कोयली नाले पर बड़े दबाव के कारण अन्य लोगों को परेशानी डोलनी पड़ रही है। दो दशक बीत चुके हैं। सबसे पहले तो जिम्मेदार कलेक्टर की जिम्मेदारी आती है। पिछले कलेक्टर से लेकर अब तक सेवा दे चुके कलेक्टर तक, यह जिम्मेदारी उन्हीं की है। अगर नाले का

जनता के लिए क्या भला कर सकते हैं? सूरत शहर के हमेशा सतर्क रहने वाले संगठन, विकास ग्राहक सुरक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, दक्षिण गुजरात के अध्यक्ष छगनलाल डी. मेवाड़ा ने वर्ष 2006 में स्थिति और मानसून के दौरान नदी के किनारे बसे नागरिकों के घरों और सामानों को हुए नुकसान को देखते हुए जनहित में वर्ष 2016 में गुजरात उच्च न्यायालय में जनहित याचिका संख्या 51/2016, 50/2016 और 34907/2022 दायर की। उस समय, गुजरात उच्च न्यायालय ने सूडान और एमएनपी के अधिकारियों और गुजरात सरकार के अधिकारियों को मौके पर निरीक्षण करने और अपनी रिपोर्ट माननीय गुजरात उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया था लेकिन शराब के नशे में चूर अधिकारियों ने उच्च न्यायालय का अपमान किया और मनमानी की, जिसके चलते गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश का आज तक पालन नहीं किया गया है। इसी वजह से आज तक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और सूरत शहर के लोग भारी परेशानी झेल रहे हैं। इसके मूल में सूरत नगर निगम, सूदा, कलेक्टर समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही का पाप है, जिन्होंने अपने कंधे बदल लिए हैं और गैँडे की खाल ओढ़ ली है।

## जैतलसर जंक्शन स्टेशन पर आधुनिक एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली (IPIS) का सफल कमीशनिंग

यात्रियों को मिलेगी रियल टाइम रेल सूचना, सूचना प्रबंधन होगा अधिक स्मार्ट एवं प्रभावी

►► संगठित-असंगठित श्रमिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं व्यवसायोन्मुखी पाठ्यक्रमों द्वारा राज्य के श्रम क्षेत्र को मिल रहा है मजबूत आधार

►► संस्थान में वातानुकूलित ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, स्मार्ट क्लासरूम, गेस्ट हाउस, ओपन एयर थिएटर, ग्रंथालय सहित अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध

गांधीनगर : राज्य में श्रमिक प्रशिक्षण और श्रम विषयक अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत महात्मा गांधी श्रम संस्थान (एमजीएलआई) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 123 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों, श्रमिक संगठनों तथा अन्य संस्थाओं के 7,211 से अधिक प्रशिक्षु सहभागी हुए। श्रम कानूनों से लेकर औद्योगिक संबंध, कार्यस्थल सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, मानव संसाधन तथा पर्यावरण प्रबंधन जैसे विषयों पर आयोजित ये प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य में श्रमिकों की क्षमता वृद्धि और कौशल विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

अहमदाबाद के गुरुकुल क्षेत्र में हरित एवं विशाल परिसर में स्थित महात्मा गांधी श्रम संस्थान 15 सितंबर, 1979 से राज्य सरकार के श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के मार्गदर्शन में एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों तथा अन्य कल्याण से संबंधित विभिन्न अनुसंधान विभागों को श्रम विषयक प्रशिक्षण प्रदान करना, श्रम संबंधी अनुसंधान करना तथा व्यवसायोन्मुखी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का संचालन करना संस्थान के प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं।

संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष 40 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया



जाता है। इनमें श्रम कानून, औद्योगिक संबंध, सामाजिक संवाद, श्रमिक कल्याण, कार्यस्थल सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता तथा बदलते श्रम कानूनों जैसे विषय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी उद्योगों तथा अन्य कल्याण से संबंधित विभिन्न अनुसंधान विभागों को श्रम विषयक प्रशिक्षण प्रदान करना, श्रम संबंधी अनुसंधान करना तथा व्यवसायोन्मुखी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का संचालन करना संस्थान के प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं।

संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष 40 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया

कार्यशालाओं तथा विशेष चर्चा सत्रों का भी आयोजन किया जाता है।

महात्मा गांधी श्रम संस्थान के भवन का डिजाइन देश के प्रसिद्ध वास्तुकार श्री बालकृष्ण विठ्ठलदास (बी. वी.) दोषी द्वारा तैयार किया गया है। इसकी स्थापत्य कला और कार्यात्मक योजना इसे विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। लगभग 12 हजार वर्ग मीटर के परिसर में स्थित इस संस्थान में 170 सीटों की क्षमता वाला आधुनिक वातानुकूलित ऑडिटोरियम, 80 सीटों की क्षमता वाला सेमिनार हॉल, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर प्रयोगशाला, गेस्ट हाउस, ओपन एयर थिएटर तथा 22 हजार से अधिक पुस्तकों से युक्त समृद्ध ग्रंथालय जैसी अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

रखने के उद्देश्य से त्रिपक्षीय सम्मेलन, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिसंवाद, संस्थान पिछले दो दशकों से विभिन्न स्नातकोत्तर एवं व्यवसायोन्मुखी

पाठ्यक्रमों का भी सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। इनमें एमए (एचआर एंड लेबर रिलेशंस), एमए (मनोविज्ञान), पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेबर लॉ एंड ब्रैक्टिस, पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, एडवांस्ड डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर कोड्स तथा विभिन्न प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और कार्यरत पेशेवरों को श्रम एवं औद्योगिक क्षेत्र में विशेष ज्ञान तथा व्यवसायोन्मुखी कौशल प्राप्त करने का अवसर मिलता है। श्रम क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संस्थान ने हाल ही में दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक विकास एवं शिक्षा केंद्र तथा इंटरनेशनल लेबर

ऑर्गेनाइजेशन (आईएलओ) के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम तथा ज्ञान के आदान-प्रदान को नई दिशा मिली है।

श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्री कंवरजीभाई बावळिया तथा राज्य मंत्री श्री कांतिभाई अमृतिषा के नेतृत्व में महात्मा गांधी श्रम संस्थान राज्य में श्रमिक प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा कौशल विकास के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। आधुनिक सुविधाओं, अनुभवी विशेषज्ञों तथा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण व्यवस्था के आधार पर संस्थान आज राज्य के श्रम क्षेत्र की अग्रणी एवं विश्वसनीय संस्था के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

वर्ष 2006 में तत्कालीन जल आपूर्ति मंत्री नरोत्तम पटेल के निर्देशों के बाद शुरू हुई बाढ़ की आपदा आज तक शरीर है। इसके बावजूद, लोग अब शासकों की आलोचना कर रहे हैं और उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन चूँकि लोग चुनावों में बड़ी संख्या में भाजपा को वोट देते हैं, इसलिए शासक अक्षम और गैर-जिम्मेदार हो गए हैं। और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। इस समस्या को देखते हुए, नागरिकों के हितों के लिए लड़ने वाले सामाजिक सेवा संगठन विकास ग्राहक सुरक्षा और अनुसंधान केंद्र के दक्षिण गुजरात अध्यक्ष छगनलाल डी. मेवाड़ा ने 2016 में गुजरात उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जो दस साल बीत जाने के बावजूद आज भी गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित है, क्योंकि अधिकारियों ने इस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

इस जनहित याचिका को दायर करने का मुख्य कारण यह है कि उकाई बांध का पानी सानिया हेमाद से कुम्भारिया, सरोली, दुनभल आदि से होकर बहने वाली खाड़ियों में जाता है। इन खाड़ियों पर बने अवैध बाजारों और बस्तियों को हटाने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत और सूदा की है, लेकिन कुम्भारिया-सरोली ग्राम पंचायत

और सूदा के नियंत्रण में आने वाली खाड़ियों में श्याम सिंगीनी टेक्सटाइल मार्केट और सारथी रैसिडेंस कुम्भारिया खाड़ी पर बने हुए हैं। कंकरापारा और सानियाग्राम से आने वाली सारथी नदी से कुम्भारिया के मोड़ पर दबाव शुरू हो गया है, जहां मीठी और कोयली खाड़ियों के दोनों किनारों पर बिल्डरों और अन्य लोगों द्वारा अवैध रूप से दुकानें, मकान और घर बनाए गए हैं। अवैध रूप से निर्मित भूमि बाजार के दूसरी ओर स्थित मागोब, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक अमर सिंह जिन्ना की सरकारी जमीन पर सरकार द्वारा आवंटित जगह का इस्तेमाल करके एससी/एसटी और सिद्धार्थ गैस एजेंसी चलाई जा रही है। आदिवासियों ने आजीविका चलाने की मांग की थी, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा आवंटित भूमि से चार गुना अधिक भूमि आवंटित की गई। उन्होंने उस पर पेट्रोल पंप बनाकर उसे बेच दिया। अब इसे 'अंबर हाउस' के नाम से जाना जाता है। यह देखकर दुख होता है कि कोयली नाले पर बड़े दबाव के कारण अन्य लोगों को परेशानी डोलनी पड़ रही है। दो दशक बीत चुके हैं। सबसे पहले तो जिम्मेदार कलेक्टर की जिम्मेदारी आती है। पिछले कलेक्टर से लेकर अब तक सेवा दे चुके कलेक्टर तक, यह जिम्मेदारी उन्हीं की है। अगर नाले का

जानकारी प्रदर्शित होगी। स्टेशन लार्ज डिस्ले बोर्ड (SLDB) पर ट्रेन का नाम, ट्रेन संख्या, आगमन एवं प्रस्थान समय तथा प्लेटफॉर्म संख्या प्रदर्शित होगी। वहीं एट ए लॉस डिस्ले बोर्ड के माध्यम से इंजन के सपेक्षकों की स्थिति, ट्रेन संख्या, आगमन एवं प्रस्थान समय तथा प्लेटफॉर्म संबंधी जानकारी उपलब्ध रहेगी।

इसके अतिरिक्त, आधुनिक पब्लिक एड्रेस (PA) सिस्टम के माध्यम से ट्रेनों से संबंधित सूचनाओं एवं उद्घोषणाओं का प्रसारण स्वचालित तथा आवश्यकता अनुसार मैन्युअल दोनों माध्यमों से किया जाएगा, जिससे यात्रियों तक समय पर सही एवं स्पष्ट सूचना पहुंच सकेगी। नई गाइडेंस डिस्ले बोर्ड के माध्यम से ट्रेन संख्या, कोच पोजीशन, प्लेटफॉर्म संख्या, स्टेशन कोड एवं रेलवे जोन की

है। इससे सूचना प्रबंधन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा तथा यात्रियों को समय पर सटीक जानकारी उपलब्ध होने से उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनेगी।

जैतलसर जंक्शन स्टेशन पर IPIS प्रणाली का सफल कमीशनिंग 08 जुलाई को संपन्न किया गया। यह परियोजना पश्चिम रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण, डिजिटल रेलवे की अवधारणा को साकार करने तथा स्मार्ट स्टेशन विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पश्चिम रेलवे का भावनगर मंडल यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक, आधुनिक एवं विश्वस्तरीय रेल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर नई तकनीकों को अपनाने तथा यात्री सुविधाओं के विस्तार के प्रति प्रतिबद्ध है।

# मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का ‘बैंक टू स्कूल मिशन’ अंतर्गत बनासकांठा के विद्यार्थियों के साथ प्रेरणादायी संवाद

► प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भावना है कि राज्य और देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

► समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बेटियों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

► मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को दिया आत्मविश्वास और उज्ज्वल भविष्य का मंत्र

► मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत से उत्साह बढ़ा, अब नियमित पढ़ाई करके अपने सपने साकार करूंगी : लाभार्थी बेंटी सुहानी

► शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित बच्चों के लिए आशीर्वाद समान बन रहा है राज्य सरकार का ‘बैंक टू स्कूल मिशन’

► राज्य में बनासकांठा जिले में 29 हजार से अधिक बच्चों का पुनः स्कूल प्रवेश

गांधीनगर : राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा स्कूल ड्राॅप-आउट दर को कम करने के दृढ़ संकल्प के साथ पूरे राज्य में ‘बैंक टू स्कूल मिशन’ चलाया जा रहा है।इस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को बनासकांठा जिले के थराद तहसील के तेनीवाडा में विद्यार्थय में पुनः प्रवेश प्राप्त करने वाले बच्चों के साथ प्रेरणादायी संवाद किया। मुख्यमंत्री ने विद्यालय में पुनः प्रवेश प्राप्त करने वाले लगभग 12 विद्यार्थियों, उनके

अभिभावकों तथा मेटर्स के साथ आत्मीय संवाद किया।उन्होंने विद्यार्थियों से सहज और आत्मीयता के साथ बातचीत की तथा बच्चों के विद्यालय छोड़ने के कारणों, पुनः प्रवेश के बाद के शैक्षणिक अनुभवों और भविष्य को लेकर उनकी आशाओं के बारे में रूचिपूर्वक जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय जाने, परिश्रमपूर्वक अध्ययन करने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने तथा जीवन में ऊँचे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए

प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी बेटियाँ घर के कार्यों की जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की क्षमता रखती हैं। उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर विशेष बल देते हुए कहा कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बेटियों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। अभिभावकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रत्येक माता-पिता का



कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को नियमित शिक्षा दिलाएँ तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भावना है कि राज्य और देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। श्री पटेल ने आगे कहा कि इसी दृष्टि के साथ उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केळवणी महोत्सव जैसी जनभागीदारी आधारित पहलें प्रारंभ की थीं; जिसके परिणामस्वरूप

आज समाज में शिक्षा के प्रति व्यापक जागरूकता उत्पन्न हुई है।उन्होंने कहा कि आज शिक्षक केवल बच्चों को पढ़ाने का ही नहीं, बल्कि विद्यालय छोड़ चुके प्रत्येक बच्चे को खोजकर पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की जिम्मेदारी भी स्कूलों पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति, परिवार और समाज के सर्वांगीण विकास का सबसे प्रभावी साधन है। यदि गरीब और सामान्य परिवार अपनी नई पीढ़ी

को शिक्षा देगे तो वे वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से बाहर निकल सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा गरीबों के लिए राशन, स्वास्थ्य तथा अन्य अनेक कल्याणकारी योजनाएँ लागू की गई हैं। इन सभी योजनाओं का वास्तविक लाभ सभी मिलेगा, जब बच्चे शिक्षित बनेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। शिक्षा द्वारा ही नई पीढ़ी का नव सृजन होगा तथा समग्र परिवार व समाज के विकास का मार्ग

प्रशस्त बनेगा। इस अवसर पर बेटियों की अभिभावक मणीबेन ने कहा कि उनकी आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियाँ अनुकूल न होने के कारण उन्हें अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़ानी पड़ी थी। गाँव के विद्यालय के शिक्षकों द्वारा समझाने तथा सरकार की योजना के अंतर्गत अब दोनों बेटियों की पढ़ाई पुनः प्रारंभ कराई गई है। इसके बाद मेरे अभिभावक समझ गए और मैंने पुनः बोर्ड परीक्षा दी। मैं बोर्ड परीक्षा में पास हुई। इसके बाद मैंने कक्षा 11 में प्रवेश लिया है। मुख्यमंत्री ने आज मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं नियमित रूप से पढ़ने जाऊँगी। वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 के दौरान विभिन्न कारणों से बीच में विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह विशेष अभियान चलाया गया है। बनासकांठा जिला कलेक्टर श्री मिहिर पटेल के मार्गदर्शन में जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षकों तथा तहसील स्तर की टीमों के सतत प्रयासों से इस मिशन के अंतर्गत राज्य में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। जिले में किए गए व्यापक सर्वेक्षण के दौरान कुल 37,415 ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान की गई थी। इनमें से 29,451 बच्चों का सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश (री-एनरोलमेंट) कराया गया है। पुनः प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 14,875 बालक तथा 14,576 बालिकाएँ शामिल हैं। इनमें से 23,032 विद्यार्थियों को गुजरात स्टेट ओपन स्कूल (जीएसओएस) से जोड़ा गया है, जबकि 6,368 विद्यार्थियों को नियमित विद्यालयों में पुनः प्रवेश दिलाया गया है। राज्य सरकार का ‘बैंक टू स्कूल मिशन’ राज्य के एक भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहने देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं आशीर्वाद समान पहल साबित हो रही है।

## बेचराजी माता जी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी: कटोसण रोड–बेचराजी रणुज रेलखंड पर पहली बार 120 किमी/घंटा की गति से सफल स्पीड ट्रायल

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के कटोसण रोड–बेचराजी–रणुज (63 किलोमीटर) ब्रॉडगेज रेलखंड का रेल संरक्षा आयुक्त (पश्चिम सर्कल) द्वारा 09 से 11 जुलाई, 2026 तक सफलतापूर्वक संरक्षा निरीक्षण सम्पन्न किया गया। यह निरीक्षण इस रेलखंड पर यात्री रेल सेवाओं के शुभारंभ की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं अंतिम तकनीकी चरण है।

तीन दिवसीय निरीक्षण के दौरान रेल संरक्षा आयुक्त ने मोटर ट्रॉली द्वारा संपूर्ण रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया। 11 जुलाई, 2026 को इस रेलखंड पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफल स्पीड ट्रायल किया गया, जिसमें रेलखंड पर सुरक्षित अधिकतम गति की भी जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान ट्रैक की गुणवत्ता, सिग्नल एवं दूरसंचार प्रणाली, पुलों, ओवरहेड विद्युत (OHE) प्रणाली, इंटरलॉकिंग, ट्रैक फिफ्टिंग, वैलायट, ओएचई की कंचाई तथा अन्य सभी संरक्षा मानकों का विस्तृत परीक्षण किया गया। अंतिम संरक्षा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत इस रेलखंड पर यात्री रेल सेवाओं का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।

इस निरीक्षण में रेल संरक्षा आयुक्त



(पश्चिम सर्कल) श्री ई. श्रीनिवास, मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) श्री प्रदीप गुप्ता, डायरेक्टर, गुजरात रेल एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (जी-राइड) श्री राजकुमार, जनरल मैनेजर (सिविल), जी-राइड श्री शिवेन्द्र कुमार, मुख्य ट्रैक इंजीनियर, मुख्य परिचालन प्रबंधक (जी) सहित निर्माण एवं ओपन लाइन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं कटोसण रोड–बेचराजी–रणुज (63 किमी) गेज परिवर्तन परियोजना को वर्ष 2017 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। लगभग 1000 करोड़ की लागत से विकसित इस परियोजना का निर्माण भारतीय रेल एवं गुजरात रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (G-RIDE) के संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत किया गया है। इस रेलखंड पर 14 रेलवे स्टेशन, 9 बड़े पुल, 100 छोटे पुल, 47 रोड अंडर ब्रिज/

लिमिटेड हाइट सब-वे (RUB/LHS) तथा 16 कर्व विकसित किए गए हैं। बेचराजी स्टेशन का धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व

इस रेलखंड का प्रमुख स्टेशन बेचराजी गुजरात के महेशाणा जिले में स्थित है, जिसे विश्वविख्यात श्री बहुचर माता मंदिर के प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया गया है। बहुचर माता मंदिर गुजरात के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने गायकवाड़ बड़ौदा रेलवे (GBR) का विस्तार बेचराजी तक कराया था।

क्षेत्र को मिलेगा आधुनिक रेल संपर्क लंबे समय तक बेचराजी क्षेत्र रेल संपर्क से वंचित रहा, जिसके कारण श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों तथा औद्योगिक इकाइयों को मुख्यतः सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता था। इस परियोजना के पूर्ण होने से नई गति प्रदान करेगी। साथ ही पर्यावरण-अनुकूल, सुरक्षित एवं सतत रेल परिवहन को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास को एक नया आयाम देगी।

संरक्षा निरीक्षण के प्रथम दिन कटोसण रोड से बेचराजी, दूसरे दिन बेचराजी से चाणसमा तथा तीसरे दिन चाणसमा से रणुज तक रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया गया। सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने तथा अंतिम संरक्षा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस रेलखंड पर यात्री रेल सेवाएं प्रारंभ करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। क्षेत्रीय विकास को मिलेगा नया आयाम इस रेलखंड के प्रारंभ होने से महेशाणा एवं पाटण जिलों के प्रमुख केंद्र बेचराजी, खोपेल एवं चाणसमा बेहतर रेल संपर्क से जुड़ जाएंगे। इससे स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों तथा उद्योगों को सुरक्षित, किफायती एवं सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही विश्व प्रसिद्ध बहुचर माता मंदिर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा अधिक सुगम बनेगी। यह रेल परियोजना क्षेत्र में रोजगार सृजन, पर्यटन, व्यापार एवं औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगी। साथ ही पर्यावरण-अनुकूल, सुरक्षित एवं सतत रेल परिवहन को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास को एक नया आयाम देगी।

## मंडल रेलवे चिकित्सालय, प्रतापनगर में फाइब्रोस्कैप, लिवर स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन

पश्चिम रेलवे के मंडल रेलवे चिकित्सालय, प्रतापनगर, वडोदरा के ओपीडी कक्ष में चिकित्सा विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ दीपाली तिवारी के मार्गदर्शन में लिवर स्क्रीनिंग (फाइब्रोस्कैन) शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों में यकृत (लिवर) संबंधी रोगों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर समय पर उपचार एवं आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराना था। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापन के अनुसार इस शिविर में कुल 67 रेलवे अधिकारी, कर्मचारी एवं आश्रितों की फाइब्रोस्कैन, जांच श्री अविनाश जगताप (BO) एवं श्री सुनील परमार (टेक्नीशियन), जाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड, डिस्कवरी डिवीजन,



वडोदरा तथा उनकी टीम द्वारा की गई। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ दीपाली तिवारी ने बताया कि फाइब्रोस्कैन एक आधुनिक, सुरक्षित, दर्दरहित एवं गैर-आक्रामक जांच पद्धति है, जिसके माध्यम से लिवर में वसा (फैटी लिवर) एवं फाइब्रोसिस (लिवर में कठोरता/क्षति) का त्वरित आकलन किया जाता है। यह जांच विशेष रूप से मधुमेह, मोटापा, फैटी लिवर, लंबे समय तक शराब के सेवन, हेपेटाइटिस-बी/सी, बड़े हुए लिवर एंजाइम तथा मेटाबोलिक सिंड्रोम से पीड़ित

व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। डॉ दीपाली के अनुसार, समय रहते लिवर रोगों की पहचान होने पर उचित जीवनशैली में परिवर्तन, नियमित चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार के माध्यम से सिरोसिस तथा अन्य गंभीर जटिलताओं से बचाव संभव है। मंडल रेलवे चिकित्सालय द्वारा समय-समय पर ऐसे स्वास्थ्य जागरूकता एवं जांच शिविर आयोजित किए जाते रहे हैं, ताकि रेलवे परिवार को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

शनिवार : सूरत में भारी बारिश और बाढ़ के कारण शहर के कई क्षेत्रों में पानी भर गया था। अचानक आई इस आपदा के समय कई औद्योगिक तथा आवासीय क्षेत्रों में पानी भर जाने से उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और रोजगार को नुकसान पहुंचा है। ऐसे समय में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने शनिवार को सूरत के द वराछ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा माह 9 प्रतिशत ब्याज पर 5 लाख रुपए तक की 'फ्लड लोन' योजना तथा बाढ़ और जलभराव से सुरक्षा प्रदान करने वाली नई बीमा योजनाओं को लॉन्च किया। सूरत शहर में हाल ही में भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुई संवेदनशील स्थिति के बीच उप मुख्यमंत्री ने सूरत के नागरिकों की जिंदादिली और संकट के समय एक-दूसरे की मदद करने की भावना को गमन किया। वराछ बैंक के मुख्य कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के



कारण हुए नुकसान का सही आकलन करने के लिए सरकार द्वारा 72 घंटे में सर्वेक्षण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। छोटी-बड़ी इंडस्ट्रीज, दुकानों और कर्मशैल इकाइयों को हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सूरत की मिट्टी में मुश्किलों से लड़ने और सकारात्मकता के साथ फिर से खड़े होने की ताकत है। उन्होंने

सरकार और स्थानीय सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर शीघ्र ही सूरत को फिर से खड़ा करने की कटिबद्धता व्यक्त की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 'आपदा के समय वराछ बैंक आपके साथ' की उक्ति को वराछ बैंक ने सही अर्थों में साकार किया है। उन्होंने संकट के समय वराछ बैंक की इस उत्कृष्ट पहल की सराहना की। मुश्किल के इस समय में वराछ को-ऑपरेटिव बैंक ने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए बाढ़ प्रभावितों के लिए मात्र 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक की 'फ्लड लोन' की घोषणा की है,

जिसके लिए उन्होंने बैंक को बधाई दी। इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल्लभाई पानशिरिया ने भी वराछ बैंक की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस उत्कृष्ट निर्णय से छोटे व्यापारियों को अधिकतम लाभ होगा। इस अवसर पर विधायक श्री प्रवीणभाई घोघरा तथा बैंक के चेयरमैन श्री नरेंद्रभाई काकडिया व श्री विठ्ठलभाई धानानी ने प्रासंगिक संबोधन किया। मुकेशभाई फेल्ल सहित अन्य आग्रणी उपस्थित रहे। योजना का त्वरित लाभ लिया जा सके, इसके लिए बैंक ने आवश्यक शर्तों की घोषणा की है : आपदा के समय सुरक्षित कल के लिए 5 लाख रुपए तक की ऋण सहायता। ऋहकों पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए ब्याज दर मात्र 9 प्रतिशत रखी गई है। ऋण की अदायगी के लिए 60 महीने

की लंबी अवधि दी जाएगी। इस ऋण को प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए वराछ बैंक के मुख्य कार्यालय में एक विशेष डेडिक्टेड स्पेस भी तैयार किया गया है, जहां से आवेदकों को त्वरित मार्गदर्शन और ऋण की मंजूरी मिल सकेगी। बाढ़ और जलभराव से सुरक्षा प्रदान करने वाली नई बीमा योजना भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा मिल सके, इस उद्देश्य से वराछ बैंक द्वारा एक विशाल जनरल इश्योरेंस (बीमा) योजना भी शुरू की गई है। इस योजना के तहत 1,000 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 10 लाख रुपए के माल के स्टॉक के लिए बीमा योजना का लाभ लिया जा सकेगा। बाढ़ या क्षेत्रों में जलभराव जैसी स्थिति में व्यापारियों के स्टॉक, गोदाम या संपत्ति को होने वाले नुकसान के विरुद्ध बीमाधारक को पूर्ण आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

## पश्चिम रेलवे द्वारा 7/11 मुंबई उपनगरीय ट्रेन,धमाकों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित



आज से बीस वर्ष पूर्व, 11 जुलाई, 2006 को मुंबई ने अपने इतिहास की सबसे दुःखद घटनाओं में से एक का सामना किया था, जब पश्चिम रेलवे के माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, सांताक्रुज, जोगेश्वरी, बोरिवली तथा भायंदर स्टेशनों के निकट सात उपनगरीय ट्रेनों के प्रथम श्रेणी डिब्बों में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे। इस दुःखद घटना की 20वीं बरसी के अवसर पर 11 जुलाई, 2026 को पश्चिम रेलवे ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। वरिष्ठ रेल अधिकारियों ने सम्मान स्वस्वयं संबंधित सातों स्टेशनों पर पुष्पक अर्पित किए तथा जान गंवाने वालों की स्मृति में दो मिन्ट का मौन रखा।

► मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 149वीं रथयात्रा की पूर्व तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा की

► 240 से अधिक छत प्वाइट, 65 ड्रोन छत 2,800 से अधिक बॉडी-वॉन कैमरों से अहमदाबाद शहर पुलिस रथयात्रा पर निगरानी रखेंगी

► 16 किलोमीटर लंबी भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा में 101 ट्रक, 30 अखाड़े और 18 भजन मंडलियाँ शामिल होंगी

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद महानगर में 6 मिनटी रथयात्राओं सहित राज्यभर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाली 230 रथयात्राओं को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए मार्गदर्शन दिया। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में परंपरागत रूप से आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथजी की 149वीं रथयात्रा, जो आगामी आषाढ़ी द्ज के अवसर पर 16 जुलाई को निकलेगी, उसे उत्साह, उमंग, शांति, सुरक्षा एवं सफलता के साथ संपन्न कराने के लिए पुलिस तथा महानगर पालिका प्रशासन की तैयारियों की शनिवार को गांधीनगर में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में विस्तारपूर्वक समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बैठक में पुलिस प्रशासन को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर निकलने वाली लगभग 230 रथयात्राएँ शांतिपूर्ण एवं सुरक्षा के वातावरण में संपन्न हों, लोग उल्लासपूर्वक रथयात्रा के दर्शन कर सकें तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पूरी सावधानी बरती जाए।



मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद में रथयात्रा मार्ग पर स्थित जंक्शन इमारतों एवं मकानों के आसपास दर्शन के लिए लोगों की भीड़ न हो, इसके लिए भी कड़ी व्यवस्था करने के निर्देशन नगर आयुक्त को दिए। अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त श्री अनुपम सिंह गहलोत ने विस्तृत प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि शहर पुलिस 'जीरो

रिस्क' की रणनीति के साथ पूर्ण सतर्कता एवं तैयारी रखते हुए 31 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ 149वीं रथयात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दिन-रात कार्य कर रही है। इस रथयात्रा में 240 से अधिक छत प्वाइट, 65 ड्रोन तथा 2,800 से

अधिक बॉडी-वॉन कैमरों के माध्यम से अहमदाबाद शहर पुलिस पूरी की पूरी, मलिक, मुख्यमन्त्री के प्रधान यात्रा पर निगरानी रखेंगी। यात्रा के दौरान अहमदाबाद महानगर पालिका के 15 मेडिकल ऑफिसर एवं 100 स्वास्थ्यकर्मी, 31 फायर वाहन तथा 237 अग्निशमन कर्मी भी तैनात रहेंगे। भगवान जगन्नाथ की 16 किलोमीटर

लंबी इस रथयात्रा में 101 ट्रक, 30 अखाड़े तथा 18 भजन मंडलियाँ शामिल होकर भक्तिमय वातावरण का निर्माण करेंगी। रथयात्रा शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित हो, इसके लिए रथयात्रा से पूर्व शहर पुलिस द्वारा शांति समिति की 69 बैठकें, मोहल्ला समिति की 79 बैठकें तथा विभिन्न संप्रदायों के धार्मिक नेताओं के साथ लगभग 178 बैठकें आयोजित की गई हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा कि इतना ही नहीं; संप्रदायिक एकता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर, रात्रिकालीन क्रिकेट एवं वॉलीबॉल मैच, लोकडायरा तथा जेन-जी के साथ संवाद कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, पुलिस महानिदेशक श्री एम. एस. मलिक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, नगर आयुक्त श्री बंचानिधि पाण्डे, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सचिव डॉ. अजय कुमार तथा क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त श्री शरद सिंघल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।